NAME → KRITI
PAPER VI → हिंदी निबंध
DATE → 15/2/2021

41/100

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

1 (3) भारत और कोविड -19

विश्व भर में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिरोशिमा नागासाकी में हुए परमाणु आक्रमण से लेकर सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि रूप में अनेक प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाएं विगत दशकों में देखी जा चुकी हैं।

परंतु साल 2020 में आए कोविड 19 नामक संदेहास्पद पूर्ण विकराल समस्या ने ना सिर्फ पूरे भारत बल्कि विश्व भर को अपने आवेष में ले लिया।

कोविड 19 एक तरह की विषाणु से होने वाली बिमारी है जो नाक, मुंह आदि के माध्यम से बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह एवं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाती है।

अधिकांश विश्व ने भूतकाल में तरह तरह की जान लेवा बिमारियों का सामना किया है जैसे कि: ब्यूबोनिक प्लेग, काला बुखार आदि जिनको खत्म होने में अनेक दशक का समय भी लग चुका है,

प्रश्न संख्या

परंतु सन् 2000 के बाद से जब पूरा विश्व तीसरी औद्योगिक औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है तथा 'मेडिकल साइंस' में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं ऐसे समय में कोविड 19 नामक बिमारी का न सिर्फ उद्गम होना अपितु पूरे मानव संसार को थमने के लिए मजबूर कर देना वास्तव में आश्चर्यचकित करने योग्य है।

भारत देश के लिए कोविड 19 से लड़ने के लिए अनेक तरह की चुनौतियाँ थी एवं भविष्य में भी रहेंगी परंतु कुछ मुख्य निम्नलिखित रही हैं :-

1. जनसंख्या : भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आती है एवं आने वाले वर्षों में भारत चीन को पीछे छोड़कर पहला पायदान प्राप्त कर लेगा। बढ़ती जनसंख्या के अपने नफा नुकसान हैं परंतु कोविड 19 जैसी महामारी से निपटने हेतु शासन की जिम्मेदारी एवं मृत्यु दर को कम से कम रखते हुए हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखना खुद में बहुत चुनौतीपूर्ण बन जाता

है। विगत एक वर्ष में जिस प्रकार भारत सरकार ने ज्यादा आबादी होने के बावजूद भारत के नागरिकों की देखभाल की है वह काबिले तारीफ है।

2 चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मचारियो की कमी → भारत में अनुभवी चिकित्सक एवं कर्मचारी जैसे नर्स, वार्डबाय आदि की काफी कमी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में तो यह अंतर और भी बढ़ जाता है। इसलिए सही समय में उचित समस्या को कोविड मरीजों तक पहुँचाना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। बहुत से चिकित्सक एवं कर्मचारी शुरुआती महीनों में ही कोविड के संपर्क में आए परंतु वह अपना कार्य सतर्कता एवं निष्ठा से करते रहे।

जनता कर्फ्यू 22 मार्च

3 लॉकडाउन एवं प्रतिबंध : हालाकि भारत ही नहीं पूरे विश्व ने लॉकडाउन को कोविड से निपटने के लिए प्रथम उपचार समझा परंतु जल्द ही उसके दुष्परिणाम आर्थिक मंदी एवं कम होते सरकारी खजाने से सरकारों पर दबाव के रूप में दिखने

24 मार्च
GDP Collapse

लगा, भारत सरकार ने भी शुरुआती 3-4 महीनों में कड़े प्रतिबंध लगाये एवं लोगों में सूचना पहुंचाई गई कि कैसे न्यूनतम संपर्क तथा आवाजाही से देश कोविड को फैलने से रोक सकता है।

परंतु लॉकडाउन खुद में एक पूर्ण औषधि नहीं है जोकि कोविड 19 को खत्म कर सकती थी, बड़े व्यवसायों तथा उद्योगों को हो रहे घाटे एवं भारत की अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट ने भारत सरकार को सितंबर माह से चरणों में अनलॉकडाउन करने को मजबूर कर दिया।

4 सामाजिक कारण → भारत में विभिन्न वर्गों में सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ पहले से ही बहुत अधिक रही हैं एवं कोविड 19 के समय में यह असमानता और बढ़ी है। मजदूर वर्ग एवं समाज का नीचला तबका लॉकडाउन से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि उनका रोज कमाने खाने का जरिया अस्थायी काल के लिए बंद हो गया तथा दो वक्त की रोटी के

लिए भटकने को मजबूर हो गया, हालांकि सरकार ने मुफ्त राशन आदि की व्यवस्था से लेकर यात्री ट्रेनें भी चलवाई परंतु यह पर्याप्त नहीं था।

5 पीपीई किट एवं मेडिकल उपकरणों की व्यवस्था → जब भारत मे कोविड 19 ने अपने पैर जमाए, भारत सरकार इतने बड़े स्तर पर पीपीई किट एवं वेंटीलेटर आदि उपकरण के साथ तैयार नहीं थी क्योंकि सामान्यतः भारत इन उपकरणों को विदेश से आयात करता रहा है एवं संपूर्ण रूप से इन कार्यों में 'आत्मनिर्भर' नहीं रहा है।

6 दिशानिर्देशों का गंभीरता से पालन तथा संचालन : स्वच्छता आदि का संपूर्ण पालन, जनता से अनिवार्य रूप से करवाना एवं दिशा निर्देशों को लोगों के लिए उन तक पहुँचाना भी एक 'टेढ़ी खीर था' (भोले के) जिसे स्थानीय प्रशासन ने बखूबी से कर दिखाया।

इस तरह अनेक चुनौतियों से लड़ते हुए एक तरफ

तो भारत सकुशल कोविड 19 के रोकथाम में लगा रहा परंतु कोविड 19 भारत के लिए अनेक तरह के अवसर भी प्रदान किया।

अवसरों के साथ साथ कोविड 19 भारतीय समाज के लिए कुछ लाभ भी प्रदान किया।

स्वच्छता आदि के मानकों में जिसके लिए भारतीय सरकार पहले से ही 'स्वच्छ भारत योजना' तथा अन्य प्रकार के स्वच्छता पखवाड़े आदि घोषित करवाता था, वह कहीं न कहीं समाज में अच्छी आदतों के रूप में खुदबखुद बस गई जैसे हाथ आदि हर 10-20 मिनट मे धोना तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, सैनिटाइजर आदि का हर थोड़ी थोड़ी देर में इस्तेमाल करना यह सब कुछ कोविड 19 से बचाव हेतु लोग स्वयं से मानने लगे एवं आने वाले समय मे यह समाज के जीवनशैली का हिस्सा भी बन जाएगा।

अवसरों की बात की जाए तो भारत के लिए 'कोविड 19'

न सिर्फ वर्तमान में परंतु आने वाले समय में भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान कायम रखने मे योगदान दे सकता है। भारत हाल मे विश्वभर में अपनी 'वैक्सीन डिप्लोमेसी' के नमूने पेश कर रहा है।

भारत के 'सीरम इंस्टीयूट' एवं 'भारत बायोटेक' विश्व भर में सबसे तथा सस्ती वैक्सीन बनाने के मामले में अपना डंका बजा रहे हैं।

अभी शुरुआती दौर में भारत बांग्लादेश, मालदीव्स, पश्चिमी एशिया के देशों मे मुफ्त में कोविड 19 की वैक्सीन मानवता हेतु भेज रहा है।

आने वाले समय में भारत इनका निर्यात भी कर सकेगा जोकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।

अन्य अवसरो में कोविड 19 भारत को अपने स्वास्थ्य बजट में सटीक रूप से एक निश्चित मुद्रा का आवंटन तथा आने वाले समय मे किसी भी विकराल परिस्थिति से निपटने योग्य

आधारिक संरचना का विकास और बेहतर ढंग से करने हेतु मौका प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी 'मनरेगा' जैसी योजनाओं का बेहतर तरीके से लागू करना भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में घर से बैठकर पढ़ाई करने के लिए भी जो सामान्य उपकरण जैसे मोबाईल, इंटरनेट आदि की जरूरत होती है वह भी भारत के पिछड़े इलाकों में उपलब्ध नहीं है, इस कारणवश कोविड 19 जैसी महामारी का सीधा प्रभाव भारत के भविष्य पर भी है। शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच शिक्षा के स्तर में जो अंतर है एवं जिसे कोविड 19 ने और भी बढ़ा दिया है उसे कम करने हेतु भारत सरकार को दृढ़ता से दूर करना होगा।

कोविड 19 पूर्ण विश्व को आपसी बैर मिटा के एक दूसरे की मदद करने तथा मुश्किल

परिस्थितियो मे भी हार न मानने के आम गुण भी परोक्ष रूप से प्रदान करता है। हांलाकि विश्व भर में कोविड 19 एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है जिसका उदाहरण हम जापान के राष्ट्रपति द्वारा स्वास्थय का हवाला देकर इस्तीफा देना हो या फिर अमेरिका मे राजनीतिक परिवर्तन एवं आने वाले समय में कोविड 19 से होनी वाली क्षति से निपटने के लिए हर देश 1) संरक्षणवाद की नीति को अपनाएगा क्योकि हर राष्ट्र को कोविड 19 से उत्पन्न विकट परिस्थतियों जैसे बेरोजगारी से लड़ना होगा परंतु दीर्घावधि में देशो के बीच परस्पर व्यवसाय एवं आदि के बढ़ने के अनुमान हैं।

भारत में कोविड 19 से लड़ने हेतु जो भागीदारी सरकार, स्वास्थ्य कर्मचारी, आमजन, पुलिस विभाग, जनसंपर्क विभाग आदि ने दिखाई हैं वह काबिले तारीफ हैं, कोविड 19 से लड़ते हुए कई अफसरों तथा कर्मचारियों ने स्वयं की जान तक गँवा दी जो वास्तव मे दिखलाता है,

कि सिर्फ किताबी ही नही अपितु जमीनी स्तर में भी भारत के जनजन में 'राष्ट्रवाद' कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके साथ साथ 'एकता में शक्ति' का नमूना बीते वर्ष मणिपुर में कुछ बिहार के मजदूरों को ले जा रही कोविड स्पेशल बस के गड़बड़ हो जाने पर पैदल चलने को मजबूर हुए मजदूरों को जूते आदि प्रदान करके दिखाई गई थी।

इस सबके बावजूद हमें कोविड 19 से सबक लेकर दीर्घावधि के लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो कोविड अभी पूर्ण रूप से खत्म नही हुआ है एवं आने वाले समय मे भी यह वापसी कर सकता है।

अंत में कोविड 19 द्वारा भारत के विभिन्न संस्थान जैसे डी.आर.डी.ओ, इसरो आदि भारत सरकार के मंत्रालयों के बीच एक नया सामंजस्य भी दिखलाया जिसके चलते नवीन उपकरण जैसे 'यूवी सैनीटाइजर' आदि बनकर तैयार हो सके, सही ही कहा गया है- 'हर चीज के दो पहलू होते हैं'

6

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

प्रश्न संख्या 2

(2) अनुशासन सभ्य समाज की धुरी

अनुशासन प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा से ही भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। एक सभ्य समाज की नींव रखने में अनुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है।

भारतीय महाकाव्यों जैसे महाभारत, रामायण भी गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किया गया है। उदाहरण: द्रोणाचार्य एवं अर्जुन तथा द्रोणाचार्य एवं एकलव्य। गुरु शिक्षा की अनुशासित परंपरा के चलते एकलव्य ने स्वयं का अंगूठा गुरु दक्षिणा द्रोणाचार्य के लिए दान कर दिया था।

सभ्य समाज में अनुशासन, व्यवहार, इज्जत, सेवा, सभ्यता आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अनुशासन के अनेक आयाम हम सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, शैक्षिक क्षेत्रों में देख सकते हैं एवं इनका महत्व भी आंक सकते

है। इनमे से निम्नलिखित है :-

आर्थिक → बिना अनुशासन के देश का आर्थिक सुधार संभव ही नहीं है। उदाहरण → आज के समृद्धशाली देश जैसे जापान एवं जर्मनी घड़ी की नोक पर अपना कार्य प्रारंभ एवं समाप्त करते हैं, वहाँ के लोगों की छवि भी इसी प्रकार से विश्व भर मे हैं तथा अन्य देश कहीं न कहीं इन देशो के ऐसे मूल्यों से प्रभावित होते हैं तथा निवेश मैं ऐसैं देशो को प्रथम स्थान देते हैं तथा व्यापार में भी इन देशों को आगे रखते हैं।

राजनीतिक → स्कैंडीनेविया देश जैसे नोर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि में सभ्यता बहुत अधिक प्रभावी हैं तथा ये देश सामाजिक बुराइयों आदि के मापदंडो में सबसे पीछे आते हैं एवं यहाँ के राजनेता भी भाषा, आचरण आदि का ख्याल रखते हुए राजनीति में भाग लेते हैं जो कि पूरे समाज मे अंदर तक संलग्न है।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान कौटिल्य एकेडमी सफलता का प्रवेश द्वार...

शैक्षिक, धार्मिक, पारिवारिक खंडो में कुछ
बच्चो को छोट से ही अच्छे मूल्यो की
जानकारी दी जाती है एवं अच्छा
व्यवहार दिखाने की सीख दी जाती है
हालांकि जिस समाज में अनुशासन की
कमी होती वहा सभ्यता, आदि से भी
परहेज किया जाने लगता है एवं वह
देश कई खंडो मे पिछड जाते हैं।
उदाहरण → पाकिस्तान : धार्मिक
अनुशासन की कमी के चलते यहा
भेदभाव बहुत अधिक है तथा हर
जमीनी स्तर के मापदंडो मे पाकिस्तान
आज पीछे है।

आज जितने भी देश
समृद्ध हैं जैसे अमरीका, आस्ट्रेलिया,
कनाडा आदि वहा एक गुण जो प्रत्यक्ष
ही दिख जाएगा वह है: अनुशासन एवं
सभ्यता।

भारत में अंग्रेजो का राज
खत्म होने के बाद सामाजिक परिस्थितियाँ
प्रतिकूल हो गई थी इसलिए आज भारत
विश्व शक्ति बनने से थोड़ा दूर है परंतु
अनुशासन तथा सभ्यता हमारी विरासत
है एवं उन्हे एहसास करते हुए हम
अपने पथ की ओर मंतव्यमान हैं।

11

3 (3) क्या लोकपाल भ्रष्टाचार को खत्म करने में सफल है ?

लोकपाल एक कानूनी संस्था है जोकि अपनी शक्तियाँ लोकपाल अधिनियम 2013 से ग्रहण करता है।

लोकपाल का ऑफिस केंद्र सरकार में हो रही भ्रष्टाचार आदि की गतिविधियों को उजागर करना है वहीं लोकायुक्त राज्य सरकार के अंदर यह काम करता है।

लोकपाल अधिनियम का पास खुद में एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि 2013 से पूर्व तरह तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे जैसे 2G घोटाला, कोलब्लॉक होटाले आदि सामने आए थे इसलिए यह उस समय के हिसाब से एक प्रशंसनीय कदम था।

अपितु लोकपाल की शक्ति पूरी तरह से भ्रष्टाचार को रोकने में विफल साबित हुई है जिसके प्रमुखतः संभावित कारण है -

1 लोकपाल की नियुक्ति → लोकपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के जज एवं गृह मंत्री आदि शामिल होते हैं, यह लोकपाल के कार्य-प्रणाली मे बाधा डालता है क्योंकि वह खुलकर कार्य नही कर पाता।

2 स्वतंत्रता की कमी → लोकपाल का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट जैसे स्वतंत्र नही है तथा इनकी कार्यप्रणाली मे हस्तक्षेप संभव रहता है।

3 विदेश संबंधी शक्तियाँ → लोकपाल के पास खुद की जाँच एजेंसी नही होती एवं वह सी.बी.आई पर जाँच आदि कार्यों के लिए निर्भर रहती हैं।

4 दण्ड संबंधी शक्तियाँ : लोकपाल जाँच मे सहयोग के लिए आरोपित को बुला तो सकती है परंतु आदेश न मानने की स्थिति मे दण्ड नही सुना सकती।

5 अन्य संस्थाओं से तालमेल की कमी : सीबीआई एवं सीवीसी आदि से

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

लोकपाल के जाँच मुद्दे उलझन एवं समय की बर्बादी की ओर चले जाते हैं।

इन सभी कारणों से लोकपाल की संस्था उतने बेहतर ढंग से अपना कार्य नही कर पाती जिसके लिए वह बनायी गई थी परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नही है कि लोकपाल, भ्रष्टाचार रोकने में विफल है।

समय समय पर लोकपाल अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर छाँपेमारी आदि की कार्यवाही करता रहता हैं एवं अनेक प्रकारो के भ्रष्टाचार संबंधी केसों को उजागर करता है।

तो यह कहा जा सकता है कि पिछले 7 साल में लोकपाल की संस्था कई निर्णायक कदम उठा चुकी है एवं जरूरत तो सिर्फ इसकी कि कैसे लोकपाल की स्वतंत्रता, निरपेक्षता, अन्य संस्थाओ के साथ तालमेल तथा शक्तियों में बढोतरी की जिससे लोकपाल भ्रष्टाचार के नियमो को कड़ाई से प्रवर्तन करे।

10